

BEFORE THE APPELLATE AUTHORITY
(Under the Right to Information Act, 2005)
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

Appeal No. 7067 of 2026

Kailash Kumar : Appellant

Vs

CPIO, SEBI, Mumbai : Respondent

ORDER

1. The appellant had filed an application dated August 10, 2026 (received by SEBI on August 13, 2026) under the Right to Information Act, 2005 (“**RTI Act**”). The respondent, by a letter dated August 20, 2026, responded to the application filed by the appellant. The appellant filed an appeal dated August 27, 2026 (Reg. No. SEBIH/A/P/26/0060, received by the Office of Appellate Authority on September 01, 2026). I have perused the application, the response of the respondent and the appeal and find that the matter can be decided based on the material available on record.
2. **Queries in the application** - The appellant, in his application, sought the following information regarding refund in PACL matter:

“अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएँ एवं अभिलेख उपलब्ध कराने का कष्ट करें—

मांगी गई 10 सूचनाएँ

1. मेरी भूमि/खसरा संख्या को **PACL Ltd.** से संबंधित संपत्ति की सूची/पोर्टल में शामिल करने का आधार क्या है? इसके संबंध में उपलब्ध आदेश, पत्र, प्रस्ताव, रिपोर्ट अथवा अन्य अभिलेख की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए।
2. मेरी भूमि को **PACL Ltd.** की संपत्ति के रूप में सूचीबद्ध करने से संबंधित फाइल नोटिंग, कार्यालय पत्राचार, अनुमोदन एवं संबंधित अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएँ।
3. मेरी भूमि का खसरा नंबर, खाता नंबर, खातेदार का नाम एवं भूमि संबंधी विवरण **PACL** के रिकॉर्ड में किस स्रोत/अभिलेख से प्राप्त किया गया? संबंधित रिकॉर्ड/दस्तावेज की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए।

4. क्या मेरी भूमि को *PACL Ltd.* की संपत्ति के रूप में दर्ज करने से पहले संबंधित राजस्व विभाग/तहसील कार्यालय से भूमि के स्वामित्व एवं राजस्व अभिलेखों का सत्यापन कराया गया था? यदि हाँ, तो सत्यापन हेतु भेजे गए पत्र तथा प्राप्त रिपोर्ट/उत्तर की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएँ।
 5. मेरी भूमि को उक्त सूची/पोर्टल में शामिल करने से संबंधित कार्रवाई किस अधिकारी/कार्यालय/समिति द्वारा की गई? संबंधित अधिकारी/कार्यालय का नाम, पदनाम तथा उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार कार्रवाई की तारीख उपलब्ध कराई जाए।
 6. मेरी भूमि को *PACL Ltd.* की संपत्ति सूची/पोर्टल में शामिल करने के संबंध में यदि कोई न्यायालय का आदेश, *SEBI* का आदेश, समिति का आदेश अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी का आदेश रिकॉर्ड में उपलब्ध है, तो उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए।
 7. मेरी भूमि को *PACL Ltd.* की संपत्ति सूची/पोर्टल से हटाने, संशोधित करने अथवा आपत्ति दर्ज कराने के संबंध में लागू नियम, प्रक्रिया, दिशा-निर्देश एवं संबंधित कार्यालय आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए।
 8. मेरी भूमि से संबंधित *PACL Ltd.* के रिकॉर्ड में उपलब्ध सभी संबंधित दस्तावेजों/अभिलेखों एवं फाइल नोटिंग की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएँ।
 9. यदि मेरी भूमि से संबंधित किसी अभिलेख में किसी बैंक, *PACL Ltd.*, समिति अथवा अन्य संस्था के पक्ष में कोई बंधक, अधिकार, दावा, रोक या अन्य प्रविष्टि दर्ज है, तो उससे संबंधित आदेश/दस्तावेज की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए।
 10. यदि मांगी गई सूचना का कोई भाग आपके कार्यालय/क्षेत्राधिकार में उपलब्ध नहीं है तथा वह किसी अन्य लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आवेदन के संबंधित भाग को संबंधित लोक सूचना अधिकारी/विभाग को स्थानांतरित करने की कृपा करें तथा इसकी सूचना मुझे प्रदान करें।”
3. **Reply of the Respondent** – The respondent, in response to the application, informed that the information sought is not available with SEBI. Notwithstanding the aforesaid, the respondent stated that all communication regarding refund status is handled by the Justice (Retd.) R.M. Lodha Committee. The respondent also advised the appellant to approach the said Committee. Further, the respondent informed that the details of PACL Matters- Public Notices, Press Releases, Status Report and FAQs etc. are available on SEBI website.
 4. **Ground of appeal** – On perusal of the appeal, it appears that the appellant is not satisfied with the response of the respondent.
 5. I have perused the application and the response provided thereto. The respondent, in his response, has categorically mentioned that the requested information is not available with SEBI. In this context, I note that the Hon’ble Central Information Commission (**CIC**) in the matter of *Sh. Pattipati Rama Murthy vs. CPIO, SEBI* (Decision dated July 8, 2013), held: “... if it (SEBI) does not have any such information in its possession, the

CPIO cannot obviously invent one for the benefit of the Appellant. There is simply no information to be given.” Accordingly, I do not find any deficiency in the response of the respondent.

6. The appellant, in appeal, has requested the instant forum to direct the respondent to transfer his application to the concerned public authority, if the information sought is not available with SEBI. I note that the responsibility of disposal of the properties and repayment to investors, is entrusted with the Justice (Retd.) R. M. Lodha Committee (under the Chairmanship of Hon’ble Mr. Justice R.M. Lodha, former Chief Justice of India), which has been constituted, pursuant to the order dated February 2, 2016 of the Hon’ble Supreme Court of India. Further, Hon’ble CIC in its decision in *M Shanmugam v CPIO, Pearls Agrotech Corporation Ltd. & Or.* (Date of decision: 14.03.2024) had accepted the contention of the respondent that the Justice Lodha Committee is not public authority under section 2(h) of the RTI Act. Accordingly, I do not find any deficiency in the action of the respondent.
7. In view of the above observations, I find that there is no need to interfere with the decision of the respondent. The appeal is accordingly dismissed.

Place: Mumbai

Date: September 21, 2026

RUCHI CHOJER

**APPELLATE AUTHORITY UNDER THE RTI ACT
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**